ईवी खरीद पर छूट एक साल बढ़ेगी

सब्सिडी की अवधि 13 अक्तूबर को हुई समाप्त

सरकार को भेजा गया समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर सब्सिडी एक वर्ष और मिलेगी। परिवहन और औद्योगिक विकास विभाग ने ईवी पॉलिसी के तहत मिलने वाली इस छूट की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।

सरकार ने 13 अक्तूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी थी। इसके तहत पहले दो लाख ई-दो पहिया खरीद पर पांच हजार, पहले 50 हजार तीन पहिया ईवी पर 12 हजार और पहले 25 हजार चार पहिया ईवी खरीद पर एक-एक लाख रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। इसी प्रकार पहले एक हजार ई-गुड्स वाहनों पर एक-एक लाख, पहली 400 ई-बसों पर 20-20 लाख की सब्सिडी देने का निर्णय किया गया था। सरकार की ओर से जारी शासनादेश में 14 अक्तूबर, 2022 से 13 अक्तूबर, 2023 तक छूट के आदेश दिए गए थे। इस तरह कुल 2,76,400 वाहनों की खरीद पर छूट दी जानी थी। पर, करीब एक साल की अवधि में मात्र 34 हजार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए पंजीकृत हुए। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी जरूर 14 अक्तूबर, 2022 से लागू हो गई थी, लेकिन क्रियान्वयन शुरू करने में छह माह लग गए। इसी लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। ऐसे में परिवहन विभाग ने सब्सिडी बढ़ाने का सुझाव औद्योगिक विकास विभाग को दिया था। अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ईवी पर सब्सिडी आगे एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

एक मौका यह भी

परिवहन विभाग के उपायुक्त राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि जिन लोगों ने 14 अक्तूबर, 2022 से 13 अक्तूबर, 2023 की अवधि में ईवी खरीदा है और सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है तो वे परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

यूपी में इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण जल्द

■ योगी बोले- ई-बसें खरीदने वालों को देंगे सब्सिडी

अयोध्या के जैन मंदिर में माता ज्ञानमती से आशीर्वाद लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संवाद

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके बाद प्रदेश के पास ई-बसों का बड़ा बेड़ा होगा। इनसे न प्रदूषण होगा, न शोर। गति भी सामान्य बसों से अच्छी होगी। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अयोध्या के रामकथा पार्क में रविवार को मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सारथी योजना का शुभारंभ करते हुए 51 बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ई-बसें खरीदने वाले व्यक्ति को सरकार प्रति बस 20 लाख रुपये सब्सिडी देगी। संवाद

>> बेटियों के हाथों में बसों की बागडोर : पेज 4